>

Title: Need to conduct a high level inquiry into the alleged misappropriation of Central funds by the State Government in carrying out construction work of dams in Bahraich Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : सभापति जी, मेरा संसदीय क्षेत्र बहराइच उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा का इलाका है। नेपाल की ओर से आने वाले पानी का सीधा प्रवेश इस जनपद में होता है जिससे प्रति वर्ष इस इलाके में भयंकर बाढ़ आती है, जिससे बहुत बड़ी संख्या में जन, धन और पशुधन की हानि होती है। बाढ़ के कारण होने वाले जल-जमाव से फसलें नष्ट हो जाती हैं, हज़ारों मकान गिर जाते हैं। इस इलाके के लोग अत्यंत गरीब व अशिक्षित हैं। जो विकास कार्य इस इलाके में होते हैं, वे बाढ़ के कारण नष्ट हो जाते हैं, जिससे इस जनपद का विकास नहीं हो पा रहा है। मैंने इस संबंध में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से लिखित अनुरोध किया तथा लोक सभा में भी सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को बाढ़ सुरक्षा तथा नदियों के किनारे पक्के तटबंध बनाने के लिए धन आबंटित भी किया गया, किन्तु उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा धन का बंदरबाँट कर लिया गया। बाढ़ से बचाने के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई। मैंने दिनांक 15 अगस्त, 2011 को बहराइच-जनपद के फख़रपुर ब्लाक में बेलहा-बहरौली तटबंध के कि.मी. 62 से 64 तक का मौके पर निरीक्षण किया। यह बाँध पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। धन की उपलब्धता के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्य ढंग से नहीं किया। मैंने हजारों उपस्थित जनसमूह के साथ श्रमदान करके लगभग दो ट्रक बोल्डर, जो मौके पर पड़ा था, बाँध के किनारे डाला। अधिकारियों द्वारा बाँध पर काम किये हुए मज़दूरों को मज़दूरी नहीं दी गई है। यही हाल बहराइच में आदमपुर-रेवली बाँध का है। जब मैंने इस मामले को लोक सभा में उठाया तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गलत तथ्यों की जानकारी दी गई कि बाँध का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि जनपद बहराइच में वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में बाँध की कटान रोकने, बंधों का निर्माण करने, पक्के तटबंध बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने कितना धन कब उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है तथा इस धन से कितना काम हुआ है, इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराई जाए तथा दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।